सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां के कारण और उपाय- धनबाद जिले का एक अध्ययन।

पीएच०डी० उपाधि हेतु अर्थशास्त्र विभाग, समाज विज्ञान संकाय में पंजीयन हेतु प्रस्तावित शोध पत्र

स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग
संकाय समाज विज्ञान

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखण्ड

2024

शोध निर्देशक
नामः डॉ० अशोक कुमार माज़ी
पदः सह-प्राध्यापक
स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय
धनबाद, झारखंड

शोधार्थी
नामः कल्पना कुमारी
एम.ए (अर्थशास्त्र), बी०एड०

शोध शीर्षक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां के कारण और उपाय- धनबाद जिले का एक अध्ययन।

सार

भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें बैंकों का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बैंकों के माध्यम से सार्वजनिक और गैर- सार्वजनिक क्षेत्रों में धन व्यवस्था का संचालन होता है और इसके माध्यम से आम लोग और व्यापारी अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं।

हाल ही में, बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। इसका प्रमुख कारण है बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाली गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वृद्धि है। यह एक चिंताजनक स्थिति है क्योंकि बैंकों की स्थिति बढ़ती हुई गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के कारण कमजोर हो सकती है और इससे आर्थिक स्थिति में असमानता उत्पन्न हो सकती है। ये उधारी या ऋण लेनेवालों के द्वारा समय पर चुक्ता नहीं किए जाने के कारण होती हैं, जिससे बैंकों को ऋण व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए, विभिन्न कदम लिए जा रहे हैं। इनमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के कारण और उनके उपचार का अध्ययन शामिल है। इसके लिए, सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे विशेषज्ञों को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। इस शोध में, बैंकों के संबंध में सटीक और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय यादृच्छिक विधि का भी प्रयोग होगा। यह विशेष बैंकों (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ओर बैंक ऑफ इंडिया) के द्वारा चयनित 160-200 नमूनों के माध्यम से होगा, जिससे समंकों के विश्लेषण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।

इस प्रयास के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के साथ जुड़े आर्थिक समस्याओं के समाधान का मार्गदर्शन किया जा सकता है और यह आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नीतियों को और भी प्रभावी बना सकता है।

परिचय

“ब्रिटिश शासनकाल” यह शब्द सुनते ही कई नकारात्मक दृश्य आँखों के सामने उभर आते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उस काल-खंड के कई सकारात्मक पक्ष भी है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं जैसे भारतीय रेलवे, औधोगिकरण आदि, उन्हीं में से एक है भारतीय बैंकिंग प्रणाली। 18 वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई तथा कलकत्ता में कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की थी, जो आधुनिक बैंको की भांति कार्य किया करते थे। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से एलेक्ज़ेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसके बाद तीन प्रेसिडेंसी बैंको की स्थापना की गई , सन 1806 मैं बैंक ऑफ बंगाल, सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। 1921 में इन तीनों बैंको को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई ओर 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। सीमित देयता के आधार पर सन 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से भारतीय और देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था।

1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना भारत के केंद्रीय बैंक के रुप में की गई। बाद में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंको को और अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से देश में 14 बड़े बैंको का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एक दशक पश्चात 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया।

वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी ऋण संस्थानों के अलावा 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 44 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1485 शहरी सहकारी बैंक, और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं।

देश के विकास में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की भूमिका सराहनीय रही है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो आज बैंकिंग प्रणाली लोगों की उंगलियों और जेबों तक पहुँच चुकी हैं। आज की अधिकांश जनसंख्या इस ढांचा से जुड़ कर इसका हिस्सा बन चुकी है और लोगों का जन जीवन दिन प्रतिदिन सुविधाजनक होता जा रहा है।

विकास के इस दौर के साथ साथ हमे बैंकिंग क्षेत्र में आ रही समस्याओं से भी अवगत होने की आवश्यकता है उन्हीं में से एक है नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (Non-Performing Assets)।

नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) गैर निष्पादित परिसंपत्तियां भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां माने जाते हैं जो उधारकर्ताओं द्वारा चुकाने में विफलता के कारण बैंको के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को ऐसी परिसंपत्तियों के रूप में रेखांकित किया है, जिसके लिए मूलधन और ब्याज दोनों का पुनर्भुगतान 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है। इस एनपीए वर्गीकरण के भीतर आरबीआई ने सम्पत्तियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है।

- घटिया परिसंपत्तियां या सबस्टैंडर्ड परिसंपत्तियां- बैंको द्वारा वितरित ऋणों के मूलभूत तथा उस पर देय ब्याज का पुनर्भुगतान जब दो वर्षों तक नहीं किया जाता, तो ऐसी परिसंपत्तियों को घटिया या सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियों की संज्ञा दी जाती है। बैंको द्वारा ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए नयी अनुसूची बनायी जाती है ऐसे ऋणों को कम से कम एक वर्ष तक घटिया परिसंपत्तियों के रूप में ही पहचाना जाता है।
- संदेहात्मक परिसंपत्तियां- ऐसे ऋण जो दो वर्षों तक गैर निष्पादित रहे हैं परंतु जिनके वसूल होने की संभावना है अर्थात जिन्हें क्षति परिसंपत्तियों के रूप में नहीं मान लिया गया है संदेहात्मक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। इस वर्ग में अधिकांश ऐसी बीमार कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण आते हैं जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया जाता है और बोर्ड द्वारा उक्त कंपनियों के पुनर्निर्माण का पैकेज अपेक्षित होता है।
- क्षति परिसंपत्तियां- ऐसी परिसंपत्ति क्षति परिसंपत्ति कहलाती है जिसकी पहचान क्षति के रूप में कर ली गई है परंतु उसे अभिलेखित नहीं किया गया है। ये वो ऋण होते हैं जो वसूल किए जाने की स्थिति में नहीं होते यद्यपि इनका कुछ न कुछ निरस्तारण मूल्य अवश्य हो सकता है।

झारखंड राज्य के अंतर्गत

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां "प्रभात खबर" समाचार पत्र में 31 दिसंबर 2023 तक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको के अंतर्गत लगातार गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि हो रही है और लगभग यह आंकड़ा 7,42,800 से 6,00,00,000 तक पहुँच चुका है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, आवास, शिक्षा और MSME आदि क्षेत्रों से बैंको की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि दर्ज हो रही है।
2. धनबाद जिला के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार धनबाद जिले में कार्यरत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र मैं बैंको की कुल संख्या लगभग 32 बताई गई है और उनकी 277 शाखाएं। धनबाद जिले के कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की गैर निष्पादित परिसंपत्ति के मामले में बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का स्थान सबसे ऊपर है।

शोध सीमा

गैर निष्पादित परिसंपत्तियां पर शोध के लिए धनबाद के संदर्भ मैं उपयुक्त सूचना और संसाधनों की उपलब्धता की कमी इसमें रुकावटें पैदा कर सकती हैं। शोधक्रिया विधि और तकनीकी त्रुटियों के कारण शोध में नतीजों की निर्धारितता पर प्रभाव आ सकता है, इसलिए, इस शोध में इन सीमाओं को उचित रूप से समझते हुए उपयुक्त विधि और तकनीकी लिया जाएगा ताकि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां के परिणामों की सही स्थिति और उनके आर्थिक प्रभाव को समझा जा सके।

अंत में, प्रस्तावित शोध में धनबाद जिले में के अंतर्गत यादृच्छिक विधि के द्वारा कार्यरत बैंको का चुनाव किया जाएगा और इस शोध में अध्ययन का प्रयास किया जाएगा।

शोध दायरा

इस शोध का दायरा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के भारतीय बैंकिंग उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए बनाई गई है। शोधकर्ता विशेष रूप से धनबाद जिले के बैंकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इस जिले के सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्र के बैंकों पर गौर करने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता देंगे। पिछले पांच वर्षों (2019-2024) के दौरान एनपीए के प्रसार का विश्लेषण किया जाएगा। शोध के प्राथमिक डेटा में बैंक कर्मचारियों और एनपीए के मामलों से जूझ रहे ऋणदाताओं के

साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार और सर्वेक्षण शामिल होंगे। इन स्रोतों से मिली जानकारी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा व्यक्तिगत बैंकों द्वारा जारी की गई प्रकाशित रिपोर्टों के द्वितीयक डेटा के साथ सम्मिलित किया जाएगा। इस शोध के माध्यम से धनबाद जिले के बैंकों में एनपीए के मौजूदा स्तर और रुझानों को समझने, इस समस्या के प्रमुख कारकों को समझने, एनपीए की समग्र समस्या में सुधार की रणनीतियों का मूल्यांकन करने और बैंक ऋण प्रक्रियाओं पर एनपीए के प्रभाव को मापने का लक्ष्य रखते हैं।

शोध की अवधि

प्रस्तावित शोध कार्य की अवधि को 3.5 वर्षों से 5 वर्षों तक अध्ययन का आलोचनात्मक प्रयास किया जाएगा। इस समयावधि के दौरान, गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों के संबंध में वर्तमान और पिछले पाँच वर्षों के आंकड़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य बैंकों में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या के पीछे छिपी योजनाओं और प्रबंधन में नए दृष्टिकोणों की खोज करना है। इस अध्ययन से हम परिसंपत्तियों की न्यूनतम स्तरों की निगरानी करने, सुधारने और बैंकों को न्यूनतम आंकड़ों में सुरक्षित रखने के लिए रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। यह अध्ययन विभिन्न आर्थिक प्रणालियों के साथ नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट्स के प्रबंधन में नई दिशाएँ प्रस्तुत करने का प्रयास होगा।

शोध की समस्या

धनबाद जिले में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ रही गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या एक चिंता का कारण बन रही है। इस समस्या के चलते बैंकों की वित्तीय स्वास्थ्य पर लगातार बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जिलास्तर पर विकास का मार्ग भी प्रभावित हो रहा है। बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करने में अधिकांश समय लगता है, क्योंकि इस जानकारी को बैंक अधिकारियों द्वारा साझा करना सामान्यत: नहीं होता है। इस अध्ययन के माध्यम से हम इस समस्या के कारणों को समझने और समाधान करने का प्रयास करेंगे, ताकि जिले में स्थानीय विकास को प्रोत्साहित किया जा सके और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।

शोध क्षेत्र में वर्तमान स्थिति

भारतीय बैंकिंग उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने में, सार्वजनिक और गैर-सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना पर आधारित अध्ययन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का बोझ अधिक है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक का क्रम सबसे ऊपर है, जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की बढ़ती संख्या में आगे है और यह कमजोर प्रबंधन की प्रवृत्ति को दिखाता है।

इसके अलावा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2023 के अनुसार, बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में गिरावट की दर दर्ज की गई है। रिपोर्ट बताती है कि शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात 1.0% घटकर आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बैंकों के लिए सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात 10 साल के नीचे 3.9% तक चला गया है, जो संकेत है कि इस क्षेत्र में व्यापक वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।

साहित्य समीक्षा:

Agrawal, V., & Magar, A. (2023).

यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें कारण, परिणाम, और सुधार के उपायों पर ध्यान केंद्रित है। इसमें नियामक ढांचाएँ, जोखिम मूल्यांकन, कानूनी चुनौतियाँ, ऋणदाता संबंधित मुद्दे, और NPAs के बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव को बताया गया है। दस्तावेज़ में यह बताया गया है कि NPAs संबंधित संकट को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए नियामक ढांचाओं के सतत सुधार, वित्तीय रिपोर्टिंग में स्पष्टता, नैतिक व्यापार प्रथाएं, और प्रभावी समाधान तंत्रों की आवश्यकता को कुँजी में रखता है। सुझावों में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट्सी ढांचाओं में सुधार, कानूनी प्रक्रियाओं को संघटित करना, और नियामक निकायों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने जैसे सुझाव शामिल हैं। यह अनुसंधान प्रमुख ऋण प्रदान प्रथाओं, मजबूत जोखिम प्रबंधन, और एक अनुकूल नियामक पर्यावरण की महत्वपूर्णीयता को रेखांकित करता है जो NPAs को कम करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।

Wadekar, V. (2012).

गरीबी के समापन का कार्य सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक कठिन चुनौती है। भारत सरकार ने इस समस्या का सामना करने के लिए कदम उठाया, जिसका पहला कदम 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण के साथ लिया गया। पिछले 40 वर्षों में रोजगार उत्पन्न करने और गरीबी को समाप्त करने के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कई ऐसी आय उत्पन्न करने वाली योजनाएं हैं जो पात्र गरीब लोगों का वित्तपोषण करने के लिए हैं, लेकिन ये असफल रही हैं। बैंकों द्वारा दी गई ऋणें अक्सर नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) में बदल गई हैं, जो भारत सरकार के द्वारा अपेक्षित परिणामों को पैदा करने में असफल रहीं हैं। यह जटिल प्रक्रिया में जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी), बैंक, और ऋणार्थी शामिल हैं। राज्य और केंद्र स्तर पर कई अध्ययनों ने सिर्फ एक पहलु को देखते हुए मुद्दों का समाधान नहीं किया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए अनुसंधानकर्ता, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में लगभग 28 वर्षों तक कार्य कर चुके हैं, सुझाव प्रदान करते हैं।

Velmurugan, R. (2013).

स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली एक अर्थव्यवस्था के बिना किसी रुकावट के विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। ऋण को मंजूरी देना और उसे वसूलना एक बैंक के मुख्य कार्यों में से एक है। यदि वसूलन में कोई असफलता होती है, तो यह बैंकों और राष्ट्र को प्रभावित करेगी। यहाँ की अध्ययन ने तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक शाखाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इस अध्ययन में 214 शाखाएं शोध इकाइयों की गठन करती हैं। डेटा प्रश्नोत्तरिकाओं के माध्यम से एकत्र किया गया था। डेटा का विश्लेषण करने के लिए ANOVA और Chi-square परीक्षणों का उपयोग किया गया। परिणाम दिखाते हैं कि शाखा की आयु, शाखा के

प्रकार, ऋण के प्रकार, ऋण की जोखिम, उधारकर्ताओं द्वारा अक्सर निकालने की प्रवृत्ति, गारंटी आवाहन और चुकता करने की योजना में परिवर्तन, एनपीए के स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं। एनपीए के खतरे को कम करने के उपयुक्त रणनीतियों की सुझाव भी इस अध्ययन में दी गई हैं।

Dhanabhakyam, M., & Shobanagetha, K. (2014).

ग्रामीण विकास देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) भारत में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। RRBs ने अपने बड़े नेटवर्क के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्र तक अधिक पहुँचा है। RRBs ग्रामीण स्तर पर प्रमुख वित्तीय संस्थान हैं जो विभिन्न प्रकार के कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की कई ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। RRB का मुख्य उद्देश्य बचत निवेश के हाथों को प्रोत्साहित करना भी है, जो उन्हें वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम लागत पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। वर्तमान में, अधिकांश RRBs को सुधार देरी, नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) की पुनर्प्राप्ति और अन्य समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, इस अध्ययन का उद्देश्य है 2004-05 से 2012-13 के दौरान RRBs नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के आंकलन करना। अध्ययन के परिणाम दिखाते हैं कि भारतीय RRBs में ग्रॉस और नेट एनपीए में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है और बैंक कृषि के लिए अधिक क्रेडिट प्रदान करते हैं।

Kumar, H. (2015).

सहकारी बैंक भारतीय वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आज ग्रामीण वित्त में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहकारी बैंकों की स्थापना वित्तीय समावेशन में सहायक होती है और इन्हें भारतीय सहकारी कंपनियों एक्ट के तहत पंजीकृत किया जाता है। ये बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और उनकी गतिविधियाँ बैंकिंग एक्ट (1949) और बैंकिंग कंपनिय़ों एक्ट (1965) के अनुसार नियंत्रित होती हैं। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली नॉन परफॉर्मिंग गतिविधियाँ (एनपीए) बैंकों के लाभ, इक्विटी, और परिसंपत्ति को प्रभावित करती हैं। आजकल, असक्रिय गतिविधियाँ बैंकिंग क्षेत्र और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए चिंता का कारण हैं। एक ऋण जो घोषित मुख्य राशि को पूरा नहीं करता, उसे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। इस अनुसंधान में, अनुसंधानकर्ता ने विभिन्न प्रकार के एनपीए और उनके कारणों को समझने का प्रयास किया है, जो बैंकिंग उद्योग के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालते हैं।

Gopi, E., & Paulraj, J. V. (2015).

यह शोध पत्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के कारणों और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के पीछे के कारणों को समझने और उनके परिसंपत्ति गुणवत्ता पर प्रभाव को उजागर किया गया है। अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान विधियों का उपयोग करता है और मुख्य डेटा एक संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया है। परिणाम सुझाव देते हैं कि तत्व जैसे नियंत्रण फिक्स्ड संपत्तियों, उप-मानक संपत्तियों, उधार और उधार धन, और क्रेडिट साइक्लिंग एनपीए को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, अध्ययन बैंकों में प्रभावी निरीक्षण प्रणालियों की आवश्यकता को उजागर करता है ताकि संभावित एनपीए के चेतावनी संकेतों की पहचान की जा सके। यह भी मुद्रास्फीति दरों के प्रभाव और एनपीए पर क्षेत्रीय विश्लेषण पर चर्चा करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गैर-प्राथमिक क्षेत्र से एनपीए में महत्वपूर्ण योगदान है। समग्रत: यह पत्र भारत में बैंकों की लाभकारीता, नकदता और क्रेडिट गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एनपीए का प्रबंधन करने के महत्व को जोर देता है।

Kiran, K. P., & Jones, T. M. (2016).

यह अध्ययन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाभकारकता पर नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अनुसंधान ने दिखाया कि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के कारण बैंकों के लाभ पर कैसे असर पड़ता है। यह अध्ययन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर किए गए अध्ययन में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) और लाभकारकता के संबंध के बारे में विशेष खुलासे किए। इस अध्ययन ने साबित किया कि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के उच्च स्तरों का वित्तीय प्रणाली और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा, यह अध्ययन ने बैंकों के लाभकारकता और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के बीच संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इससे स्पष्ट होता है कि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के उच्च स्तरों का वित्तीय प्रणाली और देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही, यह अध्ययन ने बैंकों के लाभकारकता और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के बीच संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इससे स्पष्ट होता है कि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के उच्च स्तरों का वित्तीय प्रणाली और देश की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही, यह अध्ययन ने बैंकों के लाभकारकता और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के बीच संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

M., & Ganesh, A. (2019).

बैंकों की भूमिका एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे-जैसे वे बढ़ते हैं, उन्हें ऋण, लिक्विडिटी, ब्याज, बाजार, परिचालन, और प्रबंधन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ऋण की वसूली एक महत्वपूर्ण जोखिम है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) पर असर डालती है। एनपीए की स्तर में कमी से दिखता है कि किसी विशिष्ट बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत किया है, जबकि एनपीए में वृद्धि बैंक की कुल लाभकारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह अध्ययन, 2014 से 2018 तक, चयनित बैंकों में एनपीए की घटनाओं की जांच करता है, जिसमें बैंकिंग उद्योग की चिंताओं और उनके देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को महत्वपूर्ण बनाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से उपलब्ध अगुआ डेटा का उपयोग करते हुए अध्ययन विश्लेषण के लिए एनोवा का उपयोग करता है। परिणाम बताते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एनपीए के माध्यम में सांख्यिक अंतर है, जिससे हाल के वर्षों में बैंकों की विभिन्न एनपीए हो सकती हैं।

Dr. Sudha, B., & Dr. Alamelu Mangai, R. (2020).

इस लेख में बैंकिंग क्षेत्र में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के महत्वपूर्ण कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह उच्च एनपीए के प्रभाव को समझने में मदद करता है और बैंकों के लिए वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले उपायों पर भी प्रकाश डालता है। लेख में सरकार द्वारा किए गए पुनर्पूंजीकरण योजनाओं का भी उल्लेख है जो बैंकों के पूंजीकरण के अंतर को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही, बैंकों द्वारा अपनी एसेट गुणवत्ता और लाभकारीता में सुधार करने के लिए कुछ मुख्य रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इस लेख ने बैंकों के सामूहिक वित्तीय स्थिरता पर गहरा प्रभाव डालने वाले NPAs के मुख्य कारणों को समझने में मदद की है और समस्या को संभालने के लिए उपायों की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया है।

Agrawal, R. B., & Goyal, M. (2021).

यह बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से किसानों के मामूली और सीमांत किसानों के साथ। इसमें बैंकों में नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के वृद्धि के मुख्य कारण, Covid-19 महामारी का बैंकों की एनपीए स्थिति पर प्रभाव, और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के मुद्दों का समाधान करने के लिए संभावित उपाय या रणनीतियों का विवेचन किया गया है। यह दस्तावेज़ बैंकों के आगे आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ उनके समाधान के बारे में एक समृद्ध समीक्षा प्रदान करता है। इसमें विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है जो बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) के मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। इसमें किसानों के वित्तीय संकट, बैंकों और किसानों के बीच संचार की कमी, सरकारी ऋण माफी नीतियों का प्रभाव, और अन्य अविकसित क्षेत्रों के ऋणों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) पर प्रभाव के बारे में भी

चर्चा की गई है। यह बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है और उनके समाधान के लिए सुझाव दिए हैं।

Reserve Bank of India. (2022).

वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियों का सामना है: धीमे विकास की संभावनाएं; बड़ा सार्वजनिक ऋण; बढ़ती आर्थिक विखण्डन; और लंबे समय तक बढ़ते भौगोलिक संघर्ष। भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू वित्तीय प्रणाल बलशाली बनी हुई हैं, मजबूत मैक्रोआर्थिक आधार, वित्तीय संस्थानों की स्वस्थ शीटें, शांत किसान, सुधारते हुए बाह्यिक क्षेत्र स्थिति और जारी रहने वाले आर्थिक संघटन के समर्थन से। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पूंजी भरा होने का अनुपूर्वी और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपूर्वी दिसंबर 2023 में लगभग 16.8 प्रतिशत और 13.7 प्रतिशत था। एससीबी के कुल नॉन परफॉर्मिंग गतिविधियाँ (जीएनपीए) अनुपूर्वी सितंबर 2023 में 3.2 प्रतिशत तक और नेट नॉन परफॉर्मिंग गतिविधियाँ (एनएनपीए) अनुपूर्वी सितंबर 2023 में 0.8 प्रतिशत तक घटता रहा। क्रेडिट जोखिम के लिए मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट दिखाते हैं कि एससीबी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का पालन कर सकेंगे, सिस्टम स्तर पर सीआरएआर सितंबर 2024 में यथासूची, माध्यम और कठिन तनाव स्थितियों के तहत क्रमशः 14.8 प्रतिशत, 13.5 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत पर प्रस्तुत होगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के सहारे सीआरएआर 27.6 प्रतिशत, जीएनपीए अनुपूर्वी सितंबर 2023 में 4.6 प्रतिशत और एसेट्स के ऊपरी लाभ (आरोए) सितंबर 2023 में 2.9 प्रतिशत में सुधार हुआ।

शोध उद्देश्य-

- इस शोध का उद्देश्य धनबाद ज़िले के संदर्भ में बैंको में बढ़ रही गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मूल कारणों को ज्ञात करना है।
- इस शोध का उद्देश्य बैंकिंग और जिलों के व्यापक अर्थव्यवस्था पर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से पड़ने वाले प्रभावों की जांच करना है।
- इस शोध का उद्देश्य गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बढ़ते संकट को कम करने की उपायों और प्रभावी रणनीतियों का प्रस्ताव करना है।
- इस शोध का उद्देश्य बैंको की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है।

शोध परिकल्पना

H0. बढ़ रही गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और बैंकों के शुद्ध लाभ के बीच कोई सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

H1. गैर निष्पादित परिसंपत्ति और शुद्ध लाभ में बदलाव के बीच कोई सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

H0. बैंकों की बढ़ रही गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवक्ता पर सांख्यिकी रूप से कोई प्रभाव नहीं है।

H1. बैंकों की बढ़ रही गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवक्ता पर सांख्यिकी रूप से कोई प्रभाव नहीं है।

शोध प्रश्न-

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या के आधार पर कौन-कौन से कारण हैं?
- गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का बैंकों की लाभप्रदता पर कैसा प्रभाव होता है और इससे कैसे बदलता है?
- बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का कैसा प्रभाव होता है और इससे बैंक की सामरिक स्थिति पर कैसा असर पड़ता है?
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियां गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले अधिक होने के पीछे के कारण क्या हैं?
- गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए कौन-कौन से नए उपाय हो सकते हैं?
- गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में बैंक कर्मचारियों की दृष्टिकोण क्या है और उनके अनुभवों से हमें कौन-कौन सी सीखने योग्य बातें मिल सकती हैं?
- बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन में तकनीकी सुधार के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
- धनबाद जिले के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की विशेष स्थिति के कारण, इसका स्थानीय प्रभाव और वित्तीय क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है, इस पर विचार करने के लिए कौन-कौन से अध्ययन किए जा सकते हैं?

शोध अंतराल

सार्वजनिक क्षेत्रों के गैर निष्पादित परिसंपत्ति के कारण और सुधार के उपायों से संबंधित कई शोध समय-दर-समय हुए हैं। विभिन्न शोध कई आयामों को भी प्रदर्शित करते हैं इसके बावजूद भी धनबाद जिले में संबंधित विषय से शोध अंतराल है प्रस्तावित शोध इसका तुलनात्मक एवं व्यष्टि स्तरीय अध्ययन करने का प्रयास होगा। धनबाद जिले में बैंकिंग एनपीएस मुद्दे पर समाधानात्मक शोध की सीमित उपलब्धता है जिसने विकास के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला है। इस संदर्भ में, धनबाद जिले के बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस के मुद्दे की उत्कृष्ट विश्लेषण की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय बैंकों के ऋण प्रबंधन और विकास कार्यों पर उसके प्रभाव को समझा जा सके। इस शोध के अंतर्गत, आवश्यकता है कि समाधान निरूपित करने के लिए स्थानीय बैंकों के संगठनात्मक प्रणाली, क्रेडिट प्रस्तावना, और ऋण पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया की पुनरावलोकन किया जाए। इससे नए सुझाव निकाले जा सकेंगे जो इस क्षेत्र में समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकते हैं, और स्थानीय विकास के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिल सकता है ।

शोध डिजाइन और विधि प्रणाली

शोध प्रकार

इस शोध को विवेचनात्मक बनाए रखने के लिए विवेचनात्मक शोध के रूप में वर्णन किया जाएगा, जिससे धनबाद जिले के बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की स्थिति को समझा जा सके।

नमूना का आकार

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से यादृच्छिक विधि से चुने गए 160-200 नमूना लेने का योजना बनाई जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शोध सामान्यीकृत है।

प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा

शोध की प्रारंभिक चरण में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा संग्रहण की तकनीकों को स्पष्टता से व्यक्त किया जाएगा। साकारात्मक शोध के लिए स्वरूपण का उपयोग होगा, जिसमें साक्षात्कार, सर्वेक्षण, और अन्य तकनीकें शामिल हो सकती हैं।

साकारात्मक और विवेचनात्मक दोनों प्रकार के शोध में द्वितीयक आंकड़ा का उपयोग होगा और साथ-साथ प्राथमिक आंकड़ा का भी संकलन किया जाएगा। इससे स्वतंत्रता से सत्यापित और विश्वसनीय नतीजे प्राप्त किए जा सकेंगे।

शोध में प्रयुक्त होनेवाले चर

प्रस्तावित शोध पत्र में स्वतंत्र और आश्रित, दोनों प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाएगा। चरों की सूची इस प्रकार है।

- गैर निष्पादित परिसंपत्तियां
- बैंकों की संपत्तियों की गुणवत्ता
- शुद्ध लाभ
- विकास एवं अर्थव्यवस्था
- उधार कर्ता
- ऋण

शोध उपकरण

शोध में विभिन्न उपकरणों का उपयोग होगा जैसे कि K2 परीक्षण, टी-परीक्षण, जेड परीक्षण, सूचकांक संख्या, सह-संबंध।

शोध स्वतंत्र और आश्रित चर- शोध मैं स्वतंत्र और आश्रित चर को स्पष्ट रूप से पहचाना जाएगा, जिससे समझा जा सके कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन में कौन-कौन से स्वतंत्र और आश्रित चर शामिल होंगे।

यह विधिप्रणाली शोध को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करेगी, जिससे शोध में विश्वसनीय और प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे।

शोध का महत्व

आधारभूत तथ्यों पर यह शोध समझने का प्रयास कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन की समस्या के पीछे कौन-कौन से कारण हैं और इसका बेहतर परिचय कैसे हो सकता है। यह शोध सार्वजनिक और गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता, पूंजी संरचना, और समर्थन क्षमता के संबंध में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को गहराई से जांचने का उद्देश्य रखता है।

गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का संबंध बैंकों की लाभप्रदता के साथ और इसके बदलते परिस्थितियों के साथ कैसे होता है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। यह शोध व्यापक रूप से बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रभाव को समझने के लिए विशेषता रखता है और इससे बैंक की सामरिक स्थिति पर कैसा असर पड़ता है।

इस शोध से यह समझने में सहायता मिलेगी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संबंध में बैंक कर्मचारियों की दृष्टिकोण क्या है और उनके अनुभवों से हमें कौन-कौन सी सीखने योग्य बातें मिल सकती हैं। इससे व्यवसायिक निर्णय लेने के लिए नए उपायों का पता लगाने में उपयोगी होगा जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार की दिशा में साहायक हो सकते हैं।

भविष्य कार्य

बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर शोध के पूर्ण होने के बाद, आगामी कार्य का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रकाशनों और सम्मेलनों के माध्यम से अध्ययन के परिणामों का प्रसार करना है। साथ ही, बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए नीतियों के प्रभाव और सुझावों का विस्तार से विश्लेषण होगा। वित्तीय संस्थानों, नीतिनिर्माताओं, और शोधकर्ताओं के साथ सहयोगी प्रयासों का पीछा किया जाएगा ताकि सुझाए गए रणनीतियों को कार्यान्वित किया जा सके। उद्देश्य यह है कि बैंकिंग उद्योग के भीतर एनपीए का प्रबंधन करने में सुस्त वित्तीय स्थिति और सतत प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया जाए। इस क्षेत्र में चिरपरिचित और वित्तीय नीतियों और अभ्यन्तरण की सुधार पर आधारित और अभिवृद्धि के लिए यह निरंतर संलग्न रहेगा।

वर्तमान ज्ञान में योगदान

यह शोध स्वास्थ्यपूर्ण और विकसता नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्य के रूप मैं सार्वजनिक और गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की दिशा में योगदान देना है। यह शोध धनबाद जिले के संदर्भ में बैंकों में बढ़ रही गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मूल कारणों को पहचानने उन परिस्थितियों पर अकादमिक रूप से प्रकाश डालते हुए अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचना करेगा। इसके साथ ही, शोध का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग और जिलों के व्यापक अर्थव्यवस्था पर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रभाव की जाँच करना है और मूल कारणों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिसतिथियों को समझने का लिए एक शोध आधारित संरचना देना है। शोध गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बढ़ते संकट को कम करने के उपायों और प्रभावी रणनीतियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मकसद रखता है। इस शोध से बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विश्लेषण होगा। यह शोध नई जानकारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए सुधार की संभावनाओं को उजागर करना है।

प्रस्तावित अध्यायसूची

शोध प्रस्ताव के लिए अध्यायसूची इस प्रकार से है।

- परिचय
- साहित्य समीक्षा
- गैर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का कारण
- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के कारण बैंकों की संपतियों की गुणवक्ता पर पड़नेवाले प्रभाव
- आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या
- तथ्य प्रस्तुतीकरण
- निष्कर्ष और सुझाव
- संदर्भ सूची

की वर्ड (Keyword)

गैर निष्पादित परिसंपति, सार्वजनिक बैंक, उधारकर्ता, घटिया परिसंपति, संदेहात्मक परिसंपति, क्षति परिसंपति, बी आई एफ आर जोखिम प्रबंधन, ऋण, ऋणदाता।

संदर्भ सूची

1. Wadekar, V. (2012). An Analysis of Factors Responsible for Non-Performing Assets of Govt. Loan Granted Through District Industries Centre. AIMA Journal of Management & Research, 6(4/4).
2. Velmurugan, R. (2013). Non-performing Assets: PSB. SCMS Journal of Indian Management, July - September, 26-33.
3. Dhanabhakyam, M., & Shobanagetha, K. (2014). A Study on Non-Performing Asset Management in Regional Rural Banks in India. In One Day National Level Seminar on Problems and Prospects of Rural Banking and its Impact on Empowerment of Rural Households (pp. 761-769). Sponsored by Indian Council of Social Science Research, New Delhi.
4. Kumar, H. (2015). Management of Non-Performing Assets in Central Co-Operative Banks in Haryana: An Overview. Ascent International Journal for Research Analysis, IV(II).
5. Gopi, E., & Paulraj, J. V. (2015). Causes and Remedies of Non Performing Assets Towards Indian Public Sectors Bank Management. PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH, 4(7), 144-146.
6. Kiran, K. P., & Jones, T. M. (2016). Effect of non-performing assets on the profitability of banks – a selective study. International Journal of Business and General Management (IJBGM), 5 (2), 53-60.
7. Dharmananda, M., & Ganesh, A. (2019). Non-Performing Assets: A Study on Public Sector Banks in India. Journal of Applied Management and Advanced Research, 1(2), 12-17.
8. Dr. Sudha, B., & Dr. Alamelu Mangai, R. (2020). Non-Performing Assets: Reasons And Remedies. International Journal of Scientific & Technology Research, 9(03), 1125-1127.
9. Agrawal, R. B., & Goyal, M. (2021). Non-Performing Assets of Banks: A Literature Review. PJAEE, 18(10), 330-335.
10. Reserve Bank of India. (2022). Financial Stability Report, June 2022.
11. Agrawal, V., & Magar, A. (2023). Non-Performing Assets (NPA) in Indian Banking: Causes, consequences, and remedial measures. International Journal of Research in Management, 5(2), 62-65.